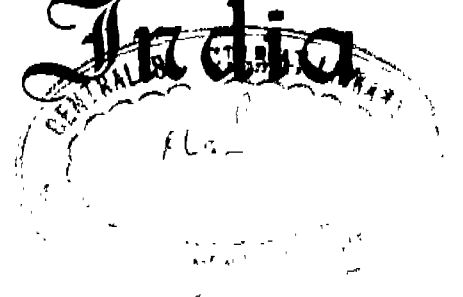




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 300 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2001/कार्तिक 29, 1923

No. 300]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2001/KARTIKA 29, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2001

सं. टीएमपी/66/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास में 'प्रति घन मीटर' के आधार पर नरम लकड़ी के लट्ठों के लिए घाटशुल्क निर्धारित करने के बारे में मै. गुप्ता ग्लोबल एक्विजिशन प्राइवेट लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का निपटारा करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएमपी/66/2001-सीएचपीटी

मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजिशन प्रा0 लि0

आवेदक

बनाम

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

प्रत्यर्थी

आदेश

(नवंबर, 2001 के 5वें दिन पारित किया गया)

यह मामला चेन्नई पत्तन में प्रति घन मीटर के आधार पर लकड़ी के लट्ठों के आयात के लिए घाटशुल्क निर्धारित करने हेतु मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजिशन प्रा0 लि0 (जीजीईपीएल) द्वारा दायित्व अभ्यावेदन से संबंधित है।

2. जीजीईपीएल ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- इसने भारतीय लकड़ी बाज़ार में न्यूजीलैंड से पाइन वुड ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है और कांडला पत्तन में इन लट्ठों का भारी मात्रा में आयात कर रहा है।
- दक्षिण भारत में इस किस्म को प्रस्तुत करने के लिए इसने अपना अगला प्रेषित माल चेन्नई पत्तन में उतारने की योजना बनाई है। इसका आशय चेन्नई पत्तन के माध्यम से अगस्त के अंत में सितम्बर के प्रारंभ से शुरुआत कर प्रारंभ में लगभग 5000 मी.ट. प्रति माह आयात करने का है।

- (iii) सामान्यतः भारत के अन्य सभी पत्तनों में लकड़ी के लट्ठों पर घाटशुल्क 'प्रति घन मीटर' के आधार पर वसूल किया जाता है, जबकि सीएचपीटी में घाटशुल्क 'प्रति लट्ठे' के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- (iv) मलेशिया, बर्मा आदि से भारत में लाया जाने वाला प्रत्येक लट्ठा लगभग 4 से 6 घन मीटर अथवा इससे भी अधिक माप का होता है। इसके विपरीत, पाइन वुड के लट्ठे आकार में बहुत छोटे होते हैं और लगभग 0.2 घन मीटर के ही होते हैं। अतः सीएचपीटी में प्रति लट्ठा के आधार पर वसूली से भारी लागत आएगी और इससे इस पाइन लकड़ी का आयात अव्यावहारिक हो जाएगा।
- (v) सीएचपीटी में मलेशिया के लट्ठे (औसत 5 घन मीटर) का घाटशुल्क 9.08 रुपए प्रति घन मीटर बैठता है, जबकि यदि प्रति लट्ठे की घाटशुल्क दर 45.40 रुपए मानी जाए तो पाइन वुड (औसत 0.2 घन मीटर) का घाटशुल्क 227.15 रुपए प्रति घन मीटर है।

3. जीजीईपीएल ने अपने पूर्व अभ्यावेदन में किए गए अनुरोध को दोहराते हुए दूसरा पत्र भेजा था। इसके अलावा उसने इस समय पाइन वुड के यातायात की स्थायी मात्रा का आश्वासन भी दिया है और बाद में पाइन वुड के सम्पूर्ण नौभार को चेन्नई पत्तन में लाने की अपनी योजना का संकेत दिया है।

4. इस अभ्यावेदन की प्रति सीएचपीटी और सभी संबंधित पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को टिप्पणी के लिए भेजी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है:-

#### हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स (एचसीसी)

- (i) पाइन वुड के लिए घाटशुल्क घन मीटर के आधार पर निर्धारित करने के लिए जीजीईपीएल का अभ्यावेदन पूरी तरह तर्कसंगत है।
- (ii) लट्ठे-आकार और मोटाई में समान नहीं होते। लट्ठा और कटी हुई लकड़ी हमेशा घन मीटर इकाई में बेची जाती है। इसलिए, सुझाव है कि इसका घाटशुल्क भी प्रति घन फुट अथवा घन मीटर के आधार पर निर्धारित किया जाए।
- (iii) लट्ठे मुख्यतः मंगलौर, कांडला और तूतीकोरिन पत्तन में आयात किए जाते हैं। इसलिए, इन पत्तनों पर प्रचलित दरों के साथ तुलना की जानी चाहिए।
- (iv) यदि सीएचपीटी में लट्ठों के घाटशुल्क की दरें आर्थिक रूप से व्यवहार्य निर्धारित की जाती हैं तो लट्ठों के आयात की मात्रा में वृद्धि होगी और इससे पत्तन को अधिक आय होगी।
- (v) चूंकि अभी यह विचाराधीन है अतः यह प्राधिकरण लट्ठों और लकड़ी के थिप के लिए भी घाटशुल्क निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। भारत में वन संसाधनों के कम होने के कारण कागज के उत्पादन के लिए सख्त लकड़ी की पहले से ही कमी है और इसलिए लुगदी का आयात किया जा रहा है।
- (vi) यदि लकड़ी का आयात मितव्ययी बनाया जाता है तो भारतीय पेपर मिलें इसी का आयात कर विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। इससे भारत में वन संसाधनों पर दबाव भी कम होगा।

#### तमिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स (टीसीसी)

- (i) सीएचपीटी की दरों के मान में लकड़ी के आयात पर घाटशुल्क निम्नवत निर्धारित है :-

मद सं.	नाम	इकाई	संशोधित दरें
85	दियासलाई बनाने की लकड़ी से भिन्न लकड़ी (लट्ठों में)	प्रति लट्ठा	45.40
86	लकड़ी, दियासलाई बनाने की लकड़ी (लट्ठों में)	प्रति लट्ठा	32.50
87	लकड़ी, बोर्ड, तख्ते, बल्लियाँ कड़ीदार तख्ते, कड़ियाँ रॉपटर स्लीपर, सपाट, छडेँ, स्तम्भ, चिरी हुई, आयताकार और संरक्ष लकड़ी	एक टन	39.00
88	लकड़ी, मद सं. 85, 86 और 87 में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया अन्य सामान	एक घन मीटर	36.30

(टीसीसी ने संशोधन-पूर्व दरें दर्शाई हैं। चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2000 में दरें संशोधित की गई हैं, इसलिए यह सूचना हमारे द्वारा अद्यतन कर दी गई है।)

- (ii) विचाराधीन पाइन वुड को सीएचपीटी की दरों के मान में घाटशुल्क अनुसूची की मद सं. 88 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तदनुसार, एक घन मीटर के लिए घाटशुल्क दर 36.30 रुपए (संशोधित) लागू होगी।
- (iii) घाटशुल्क का उपर्युक्त वर्गीकरण आयातकों और सीएचपीटी दोनों के लिए उपयुक्त होगा। प्रशुल्क में और परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

#### मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एमसीसी)

- (i) आवेदक का अभ्यावेदन वैध है।
- (ii) चूंकि पाइन वुड के लट्ठे सामान्य आकार के लट्ठों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं और मात्रा में भी कम होते हैं, इसलिए घन मीटर के आधार पर घाटशुल्क वसूल करने का वैध मामला बनता है।
- (iii) चेन्नई पत्तन में इस वस्तु का आयात पहली बार किया जाएगा। यह माँग नए प्लवमान शीशा उद्योगों के कारण पैदा हुई है, जिनके उत्पाद पाइन लकड़ी की पेटी में पैक किए जाते हैं।
- (iv) प्रति लट्ठे के आधार पर लागत के अनुसार घाटशुल्क वसूली इस व्यवसाय को पूर्णतः अव्यवहार्य बना देगी। इससे उन मूल उत्पादों की लागत और व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके लिए ये लट्ठे पैकिंग के सामान के रूप में दिए जाते हैं।
- (v) पाइन वुड के लट्ठों के आयात के लिए घन मीटर के आधार पर घाटशुल्क प्रभार की अनुमति दी जाए।

5. सीएचपीटी ने कोई लिखित टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। एक अनुस्मारक भेजने के पश्चात्, सीएचपीटी ने (30 अगस्त, 2001 के पत्र द्वारा) सूचित किया था कि उसके विभिन्न मण्डल कार्यालयों से संगत विवरण प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है और उनसे ब्योरे मिलने पर ही वह अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

6. इस मामले की संयुक्त सुनवाई 5 अक्टूबर, 2001 को सीएचपीटी में हुई थी। संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए थे :-

#### मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजिज प्राइवेट लिमिटेड

घाटशुल्क सामान्यतः प्रति घन मीटर आधार पर होता है। यहाँ यह 'प्रति लट्ठे' के आधार पर है। इससे हमारी लागत में बहुत अधिक वृद्धि होती है।

#### चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

- (i) हम इससे सहमत हैं। प्रशुल्क मदों 85, 86 और 88 को एक साथ मिलाया जा सकता है और 'प्रति घन मीटर' आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।
- (ii) मद 88 को विस्तारित करके 'पाइन वुड सहित' किया जाए। इसका जिस रूप में प्रयोग होता है अथवा अंततः किस प्रयोग में आता है इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए।

#### तमिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स (टीसीसी)

प्रविष्टि में बहुत अधिक बदलाव न करें। पाइन वुड को अवशिष्ट मद 88 (36.30 रुपए प्रति छत मीटर) में शामिल किया जाए।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में और संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) यह मामला घाटशुल्क प्रभारों की वसूली के प्रयोजन से पाइन वुड के वर्गीकरण का है।
- (ii) पृथक घाटशुल्क प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से सीएचपीटी की दरों के मान में लकड़ी के लट्ठों का चार श्रेणियों (मद 85, 86, 87 और 88) में वर्गीकरण किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी (मद 88) अवशिष्ट प्रविष्टि है, जिसमें घन मीटर आधार पर दर निर्धारित की जाती है। वास्तव में, यह अभ्यावेदन सीएचपीटी द्वारा पाइन वुड को मद 85 अर्थात् 'दियासलाई बनाने की लकड़ी के लट्ठों से मिश्र लकड़ी' के अंतर्गत वर्गीकरण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए घाटशुल्क दर 'प्रति लट्ठे' के आधार पर निर्धारित की गई है।
- (iii) जैसा कि जीजीईपीएल ने उल्लेख किया है, यदि 5 से 6 घन मीटर के लकड़ी के लट्ठे और 0.2 घन मीटर के पाइन लकड़ी के लट्ठे पर एक ही घाटशुल्क दर वसूल की जाती है तो यह एक विसंगति होगी।

- (iv) इस विसंगत स्थिति को सीएचपीटी ने समझा है और इसीलिए संयुक्त सुनवाई में, पाइन वुड के लट्ठों को अवशिष्ट मद (मद सं. 88) के अंतर्गत वर्गीकृत करने और घन मीटर के आधार पर घाटशुल्क वसूल करने का प्रस्ताव किया है। उसने इस मद के अंतर्गत पाइन वुड को विशेष रूप से शामिल करने के लिए इस मद के नाम की व्याख्या करने और यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाने का अनुरोध किया है कि विनिर्दिष्ट दरें ऐसे किसी उल्लेख के बिना लागू होंगी कि किस रूप में इनका प्रयोग किया जाए अथवा अंततः यह किस प्रयोग में आता है। यह अनुरोध शायद वर्गीकरण में किसी संभावित अस्पष्टता से बचने के लिए किया गया है।
- (v) संयुक्त सुनवाई के शुरु में सीएचपीटी ने तर्क दिया था कि घाटशुल्क अनुसूची में लकड़ी से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ घन मीटर आधार पर विनिर्दिष्ट की जाएँ। निःसंदेह यह एक उपयुक्त और युक्तिसंगत व्यवस्था होगी। किन्तु, यह भी उल्लेखनीय है कि पाइन वुड सीएचपीटी में पहचाना वाला नया कार्गो है, जबकि सामान्य लकड़ी के लट्ठे वर्तमान यातायात के हिस्से हैं। यदि दर में उपयुक्त समायोजन किए बिना प्रभार की इकाई में समायोजन किया जाता है तो एक घन मीटर से अधिक के सामान्य लकड़ी के लट्ठों को मौजूदा मुगतान ('प्रति लट्ठे' के आधार पर) से बहुत अधिक मुगतान करना पड़ेगा। सीएचपीटी की दरों के मान की अप्रैल 2002 में समीक्षा/संशोधन किया जाना है। दरों के मान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करते समय सीएचपीटी लकड़ी के लट्ठों पर वसूल किए जाने वाले घाटशुल्क को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर सकता है। तब तक, घाटशुल्क अनुसूची की मद 85 और 86 में वर्तमान प्रभार इकाई को जारी रखने की अनुमति दी जाती है।
- (vi) पाइन वुड (नरम लकड़ी) के आयात के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एचसीसीआई के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित व्यवस्था का समर्थन किया है।
- (vii) सीएचपीटी ने इस संबंध में प्रशुल्क उपबंधों को पूर्णतः बदलने का प्रस्ताव किया है। परंतु, उसने लगभग जनवरी-फरवरी 2002 तक प्रशुल्कों के सामान्य संशोधन के अपने प्रस्ताव को तैयार करने तक ऐसे अलग-अलग प्रयासों में भेद करने के इस प्राधिकरण के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

8.1. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीएचपीटी की दरों के मान के अध्याय-II क-घाटशुल्क; मान क-सामान्य में मद 88 में निम्नलिखित संशोधन का अनुमोदन करता है :-

मद सं.	नाम	इकाई	दर
88	लकड़ी, मद 85, 86 और 87 में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य सामान एवं पाइन वुड, भले ही उसका किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए और अंततः वह किसी भी प्रयोग में आए।	1 घन मीटर	36.30 रुपए

8.2. सीएचपीटी की दरों के मान में उपर्युक्त संशोधन किए जाने से मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजिब प्राइवेट लिमिटेड के अभ्यावेदन का स्वतः ही निपटान हो जाता है।

9. सीएचपीटी को परामर्श दिया जाता है कि वह प्रशुल्कों की अगली सामान्य समीक्षा/संशोधन करते समय लट्ठों पर घाटशुल्क से संबंधित सभी मदों को युक्तिसंगत बनाए।

10. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/143/III/IV/2001/असाधा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2001

No. TAMP/66/2001-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by M/s. Gupta Global Exim Pvt. Ltd. about fixation of wharfage for soft-timber logs on a 'per cubic meter' basis at the Chennai Port as in the Order appended hereto.

**SCHEDULE****Case No. TAMP/66/2001-CHPT**

<b>M/s. Gupta Global Exim Pvt. Ltd.</b>	<b>- - -</b>	<b>Applicant</b>
	<b>Vs</b>	
<b>The Chennai Port Trust (CHPT)</b>	<b>- - -</b>	<b>Respondent</b>

**ORDER**

(Passed on this 5th day of November 2001)

This case relates to a representation filed by M/s. Gupta Global Exim Pvt. Ltd. (GGEPL) about fixation of wharfage for import of timber logs on a per cubic meter basis at the Chennai Port.

2. In its representation, the GGEPL has made the following points:
  - (i). It has pioneered to introduce a specie called pine-wood from New Zealand in the Indian wood market; and, is importing these logs in good volume at the Kandla Port.
  - (ii). It plans to discharge its next consignment at the Chennai Port to introduce this specie in South India. It intends to import initially about 5000 M.T. every month through the Chennai Port beginning from end August /early September.
  - (iii). Normally in all the other ports of India, wharfage on timber logs is charged on 'per cubic meter' basis, whereas at the CHPT the wharfage is prescribed on 'per log' basis.
  - (iv). Each of the logs brought into India from Malaysia, Burma, etc., measures about 4 to 6 cubic meter or even more. On the contrary, pine-logs are much smaller in size and are only about 0.2 CBM. Hence, the wharfage charged on "per log basis" at the CHPT amounts to a huge cost and makes such imports of pine-wood unviable.
  - (v). Wharfage at the CHPT for the Malaysian logs (average 5 CBM) is Rs.9.08 per CBM, whereas the wharfage for pine-wood (average 0.2 CBM) is Rs. 227.15 per CBM, if the wharfage rate of Rs. 45.40 per log is considered.
3. The GGEPL has sent another letter reiterating the request made in its earlier representation. In addition it has assured steady volumes of pine-wood traffic presently and indicated its plans to bring entire shiploads of pine-wood to the Chennai Port later.
4. A copy of the representation was forwarded to the CHPT and all concerned port users / representative bodies of port users for comments. The comments received are summarised below:

**The Hindustan Chamber of Commerce (HCC)**

- (i). The representation of GGEPL to prescribe wharfage for pine-wood on CBM basis is quite logical.
- (ii). Logs are not uniform in size and dimension. Log and cut-wood are always sold in units of cubic meters. Hence, it is advisable that the wharfage for the same is also fixed on a per cubic feet or cubic meter basis.

357341/2001-2

- (iii). The logs are mainly imported at the Mangalore, Kandla and Tuticorin port. Hence, a comparison shall be made with the rates prevalent at these ports.
- (iv). If the wharfage rates of logs are made economically viable at the CHPT the volumes of log imports shall increase bringing in more income to the Port.
- (v). While this is under consideration, the Authority can also consider to fix the wharfage for Logs and Wood-Chip. With dwindling forest resources in India there is already a shortage of Hard Wood for manufacture of paper and pulp is being imported.
- (vi). If wood import is made economical, Indian Paper Mills can import the same and save foreign exchange. This will ease the pressure on the forest resources in India.

#### The Tamil Chamber of Commerce (TCC)

- (i). In the CHPT Scale of Rates, wharfage on import of timber is prescribed as follows:

Item No.	Nomenclature	Unit	Revised Rates
85	Timber (in logs) other than Match Wood logs	Each log	45.40
86	Timber, Match Wood (in logs)	Each log	32.50
87	Timber, Boards, Planks, Poles, Battens, Scantlings, Rafters, Sleepers, Planed, Rods, Posts, Sawn, Squares and manifested Dunnage.	1 Tonne	39.00
88	Timber, other materials not otherwise specified in items 85,86 and 87	1 Cubic Meter	36.30

(The TCC has indicted pre-revised rates. Since the rates have been revised by this Authority in April 2000, the information has been updated by us).

- (ii). Pine-wood, which is under consideration here, can be classified under Item No. 88 of the wharfage Schedule in the CHPT Scale of Rates. Accordingly, wharfage rate of Rs. 36.30 (revised) for 1 cubic meter will be applicable.
- (iii). The above classification of wharfage will be suitable for both the importer and the CHPT. There is no need for further change in the tariff.

#### The Madras Chamber of Commerce and Industry (MCC)

- (i). The representation of the Applicant is valid.
- (ii). Since pine-logs are smaller in size and have less volume than normal timber logs, there is a valid case to charge wharfage on CBM basis.
- (iii). The import of this commodity into the Chennai Port shall be for the first time. The demand is generated on account of the new float glass industries whose product is crated in pine-wood.
- (iv). Charging the wharfage as per the costing on per log basis shall render this business completely unviable. It shall have a cascading effect on the cost and viability of the basic products for which the logs serve as packing materials.
- (v). The wharfage charge on the imports of Pine Logs on CBM basis shall be allowed.

5. The CHPT did not furnish any written comments. After a reminder, the CHPT informed (vide its letter dated 30 August 2001) that relevant details from its various divisional offices were awaited and on receipt of them its comments would be furnished.

6. A joint hearing in this case was held on 5 October 2001 at the CHPT. At the joint hearing, the following submissions were made:

**M/s. Gupta Global Exim, Private Limited**

Wharfage is normally on a per cubic meter basis. Here it is on 'per log' basis. This increases our cost enormously.

**Chennai Port Trust (CHPT)**

- (i). We agree. Tariff items 85, 86 and 88 can be combined into one and notified on a 'per cubic meter' basis.
- (ii). Item 88 will be expanded to say 'including pine-wood'. This will be without reference to the form in which it comes or the end use.

**Tamil Chamber of Commerce (TCC)**

Do not alter the entry too much. Take pine-wood under the residuary item 88 (Rs. 36.30 per cubic meter).

7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and bearing in mind the arguments advanced at the joint hearing, the following position emerges:

- (i). This is a case for classification of pine-wood for the purpose of levy of wharfage charges.
- (ii). The CHPT Scale of Rates classifies timber logs into four categories (items 85, 86, 87 and 88) for the purpose of prescribing separate wharfage charges. The fourth category (item 88) is a residual entry against which the rate is prescribed on a CBM basis. In fact, the representation is due to classification of pine-wood by the CHPT under item 85 i.e. as 'Timber other than Match wood logs' for which the wharfage rate has been prescribed on a 'per log' basis.
- (iii). As pointed out by the GGEPL, there is an anomaly if a timber log measuring 5 to 6 CBMs and a pine-wood log measuring 0.2 CBM are levied the same wharfage rate.
- (iv). This anomalous position has been realised by the CHPT; and, at the joint hearing, it has proposed to classify pine-wood logs under the residuary item (item no. 88) and levy wharfage on a CBM basis. It has requested to elaborate the nomenclature of this item to specifically include pine-wood under this item and also to clearly indicate that the specified rates are applicable irrespective of the form in which it comes or of its end-use. This request is perhaps to avoid any possible ambiguity in classification.
- (v). Initially at the joint hearing, the CHPT argued that all the entries relating to Timber in the wharfage schedule should be specified on a CBM basis. This will no doubt be a reasonable and rational arrangement. Nevertheless, it has to be recognised that pine-wood is a new cargo to reach the CHPT whereas normal timber logs are part of the existing traffic. If an adjustment in the unit of charge is made without a suitable adjustment in the rate, normal timber logs measuring more than 1 CBM will have to pay much more than what they pay now (on a 'per log' basis). The Scale of Rates of the CHPT is due for a review / revision in April 2002. While formulating its proposal for general

revision of the Scale of Rates, the CHPT may consider rationalisation of the wharfage leviable on timber logs. Till such time, the existing unit of charge given in items 85 and 86 of the wharfage schedule is allowed to continue.

- (vi). The representatives of the HCCI, who represented the interests of pine-wood (softwood) imports, expressed their endorsement of the arrangement suggested.
- (vii). The CHPT has proposed a total revamping of the tariff provisions in this regard. It has, however, accepted this Authority's advice to defer such individualised initiatives till formulation of its proposal for a general revision of the tariffs around January-February 2002.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following modification of item 88 in Chapter II A-Wharfage; Scale A – General of the Scale of Rates of the CHPT:

Item No.	Nomenclature	Unit	Rate
88	Timber, other materials not otherwise specified in items 85, 86 and 87, including pine-wood irrespective of the form in which it comes and of its end-use.	1 cubic meter	Rs. 36.30

8.2. With the modification in the Scale of Rates of the CHPT as mentioned above, the representation of M/s. Gupta Global Exim Private Limited stands disposed of automatically.

9. The CHPT is advised to rationalise all the items relating to wharfage on logs at the time of its next general review / revision of tariffs.

10. This Order will come into effect from the date of its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman  
[Advt./143/III/IV/2001/Exty.]